

सथिल वन घोषणा

प्रलिस के लयः

सथिल फॉरेस्ट डकिलेरेशन, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्ग्रेस, SOFO 2022, FAO

मेन्स के लयः

भारत में वन संसाधनों की स्थति और संबधति चतिाँ

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में सथिल वन घोषणा को दक्षिण कोरिया के सथिल में 15वीं वशिव वानकी कॉन्ग्रेस में अपनाया गया ।

- इस घोषणापत्र पर **141 देशों ने हस्ताक्षर कये हैं** ।
- इससे पहले **संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO)** द्वारा **स्टेट ऑफ वरल्ड्स फॉरेस्ट्स 2022 (SOFO 2022)** को जारी किया गया था ।

वशिव वानकी कॉन्ग्रेस के बारे में:

- **परचियः**
 - इसका आयोजन **प्रत्येक छह वर्ष में** किया जाता है ।
 - इस कार्यक्रम को कोरिया गणराज्य एवं FAO द्वारा सह-आयोजति किया गया ।
 - यह वशिव वानकी कॉन्ग्रेस एशिया में आयोजति दूसरा कार्यक्रम है ।
 - पहली कॉन्ग्रेस का आयोजन एशिया में 1978 में हुआ जिसकी मेज़बानी इंडोनेशिया ने की थी ।
 - वशिव वानकी कॉन्ग्रेस ने इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों और भवषिय के लयि समावेशी चर्चा हेतु एक मंच के रूप में काम किया है ।
- **वर्ष 2022 हेतु थीमः** हरति, स्वस्थ और अनुकूल नरिमाण ।
- **लक्ष्यः**
 - सतत् विकास के सभी स्तरों पर वनों और वानकी के भवषिय हेतु नई दृष्टि और कार्य करने के नए तरीके अपनाना ।
 - वनों और वानकी में नविश का अर्थ है लोगों एवं उनकी आजीविका में नविश और सतत् विकास में नविश द्वारा वर्ष 2030 तक **सतत् विकास लक्ष्यों** को प्रापत् करना ।

घोषणा की मुख्य वशेषताएँ:

- **साझा ज़मिमेदारीः**
 - इस घोषणा में यह रेखांकति किया गया कविन राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सीमाओं से स्वतंत्र होते हैं जो जैव वविधिता एवं ग्रहीय पैमाने पर कार्बन, जल तथा ऊर्जा चक्रों के लयि महत्त्वपूरण हैं ।
- **वनों में नविशः**
 - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत प्रतबिद्धताओं को पूरा करने और नमिनीकृत भूमि को बहाल करने के लक्ष्यों को पूरा करने के लयि वशिव स्तर पर वन एवं वन परदृश्य बहाली में **नविश को वर्ष 2030 तक तीन गुना करने की आवश्यकता** है ।
- **चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था और जलवायु तटस्थताः**
 - वशिव वानकी कॉन्ग्रेस के दौरान निकाले गए प्रमुख नषिकर्षों में चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था और जलवायु तटस्थता को अपनाने के महत्त्व को भी रेखांकति किया गया है ।
 - घोषणापत्र में वन संरक्षण, बहाली और संधारणीय उपयोग में नविश को बढ़ावा देने के लयि नवीन **हरति वतितपोषण तंत्र** की आवश्यकता को रेखांकति किया गया एवं अक्षय, पुनः प्रयोज्य और बहुमुखी सामग्री के रूप में स्थायी रूप से वन उत्पादों की क्षमता पर प्रकाश डाला गया ।

- **भविष्य की महामारी को रोकने के लिये कदम:**
 - भविष्य की **महामारियों** के जोखिम को कम करने एवं **मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य** के लिये तथा अन्य आवश्यक लाभ हेतु स्वास्थ्य प्रदान करने वाले वनों को भी बनाए रखा जाना चाहिये।
- घोषणा में साक्ष्य-आधारित वन एवं भूदृश्य, नरिणय लेने और तंत्र को सक्षम करने के लिये उभरती हुई नवीन तकनीकों व तंत्रों के नरितर वकिस तथा उपयोग हेतु नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने का भी आग्रह कया गया।

15वीं वशिव वानकी कॉन्ग्रेस की अन्य मुख्य वशैषताएँ:

- अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये इस कॉन्ग्रेस में की गई अन्य पहलें:
 - **एकीकृत जोखमि प्रबंधन (AFFIRM) तंत्र के साथ वनों के भविष्य का आशवासन:**
 - AFFIRM का उद्देश्य अन्य देशों के लिये उदाहरण के रूप में उपयोग करने के लिये **एकीकृत जोखमि प्रबंधन** योजनाओं को वकिसति कर एक ऐसी पद्धतिका नरिमाण करना है जो देशों को अशांतजैसे जोखमि का बेहतर ढंग से मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के साथ ही वनय खतरों तथा वन-संबंधी जोखमिों की बेहतर समझ प्रदान कर सके।
 - **'वन पारसिथतिकी तंत्र की उत्पादकता को बनाए रखने (SAFE)' की पहल:**
 - **REDD+ कषमता नरिमाण के लिये मंच:**
 - REDD+ वन कषेत्र में गतविधियों का मार्गदर्शन करने के लिये 'जलवायु परविरतन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन' (UNFCCC) पार्टीज़ (COP) द्वारा बनाया गया एक फ्रेमवर्क है, जो वनों की कटाई और वन कषरण के कारण होने वाले उत्सर्जन को कम करता है, साथ ही वनों का स्थायी प्रबंधन एवं वकिसशील देशों में वन कार्बन स्टॉक का संरक्षण और उसमें वृद्धिकरता है।

वनों के लिये प्रमुख सरकारी पहल:

- **हरति भारत हेतु राष्ट्रीय मशिन:**
 - यह जलवायु परविरतन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत आठ मशिनों में से एक है।
 - इसे फरवरी 2014 में देश के जैविक संसाधनों और संबंधित आजीविका को प्रतकिल जलवायु परविरतन के खतरे से बचाने तथा पारसिथतिकी स्थरिता, जैव वविधिता संरक्षण व भोजन-पानी एवं आजीविका पर वानकी के महत्त्वपूर्ण प्रभाव को पहचानने के उद्देश्य से शुरू कया गया था।
- **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP):**
 - इसे नमिनीकृत वन भूमिके वनीकरण के लिये वर्ष 2000 से लागू कया गया है।
 - इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वति कया जा रहा है।
- **कषतपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधकिरण (CAMP Funds):**
 - इसे वर्ष 2016 में लॉन्च कया गया था, इसके फंड का 90% हसिसा राज्यों को दया जाता है, जबकि 10% केंद्र द्वारा बनाए रखा जाता है।
 - इस धन का उपयोग जलग्रहण कषेत्रों के उपचार, प्राकृतिक उत्पादन, वन प्रबंधन, वनयजीव संरक्षण और प्रबंधन, संरकषति कषेत्रों में गाँवों के पुनरवास, मानव-वनयजीव संघर्षों के प्रबंधन, प्रशकिषण व जागरूकता पैदा करने, लकड़ी बचाने वाले उपकरणों की आपूर्ति तथा संबद्ध गतविधियों के लिये कया जा सकता है।
- **नेशनल एकशन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेज़र्टफिकेशन:**
 - इसे वर्ष 2001 में मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधति करने के लिये तैयार कया गया था।
 - इसका कार्यान्वयन MoEFCC द्वारा कया जाता है।
- **वन अग्न रोकथाम और प्रबंधन (FFPM):**
 - यह केंद्र द्वारा वतितपोषति एकमात्र कार्यक्रम है जो वशेष रूप से जंगल की आग से नपिटने में राज्यों की सहायता के लिये समरपति है।

वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. 'वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन से सही हैं?

1. इसे पहली बार वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शखिर सममेलन में समर्थन दया गया था।
2. यह वनों के नुकसान को समाप्त करने के लिये एक वैश्विक समयरेखा का समर्थन करता है।
3. यह कानूनी रूप से बाधयकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा है।
4. यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और स्वदेशी समुदायों द्वारा समर्थति है।
5. भारत इसकी स्थापना के समय से ही इसके हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से एक था।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 1, 3 और 5
- (c) केवल 3 और 4
- (d) केवल 2 और 5

उत्तर: (A)

व्याख्या:

- वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा एक स्वैच्छिक और गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी राजनीतिक घोषणा है जो वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के महासचिव द्वारा प्रेरित सरकारों, कंपनियों और नागरिक समाज के बीच संवाद से विकसित हुई है। **अतः कथन 1 सही है तथा कथन 3 सही नहीं है।**
- घोषणापत्र में वर्ष 2020 तक वनों की कटाई की दर को आधा करने, वर्ष 2030 तक इसे समाप्त करने और करोड़ों एकड़ भूमिको बहाल करने का वादा किया गया है। **अतः कथन 2 सही है।**
- वर्तमान में इस घोषणा के 200 से अधिक समर्थनकर्त्ता हैं, जिनमें राष्ट्रीय सरकारें, उप-राष्ट्रीय सरकारें, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय, संगठन, गैर-सरकारी संगठन तथा वित्तीय संस्थान शामिल हैं। **अतः कथन 4 सही है।**
- वनों की स्थापना पर न्यूयॉर्क घोषणा के समय भारत इसका हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं था। **अतः कथन 5 सही नहीं है।**

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/seoul-forest-declaration>

